अफगानिस्तान

प्रभात कुमार रॉय

अमेरिका के लिए अफगानिस्तान तक़रीबन उसी तरह से तबाही का सबब बन चुका है, जैसा कि कभी पहले इतिहास में पूर्व सोवियत यूनियन के लिए बन गया था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को अफगानिस्तान में जंग करते हुए बरसों 9 साल बीत चुके हैं, किंतु अभी तक यह युद्व किसी फैसलाकुन हालत तक पंहुच नहीं सका है। अभी कुछ दिनों पहले ही काबुल के बीच बमों के भयावह धमाके करके अलकायदा और तालीबान ने अपनी अक्षुण्ण ताकत का प्रर्दशन कर दिया है। इसके पहले अमेकिन खुफिया ऐजेंसी सीआईए के नौ बड़े अधिकारियों को घात लगाकर तालीबानी हलाक़ कर चुके थे।

अब तो अमेरिका की सैन्य निराशा इस हद तक बढ़ चुकी है कि वाशिगंटन में बैठे हुए अमेरिकन शासक अब बाकायदा 'गुड और बैड' तालीबान की बातें करने लगे हैं। ताकि अमेरिका देर सबेर कथित 'गुड तालीबान' से सियासी बातचीत करके अपफगानिस्तान से इज़्जत के साथ रुख़सत हुआ जा सके। अप़फगानिस्तान में प्रायोजित आम चुनावों में सामने आई जबरदस्त धंधली ने तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के कथित प्रजातंत्रिक प्रेम का एक बार पुनः बेनक़ाब करके रख दिया है और अमेरिका की कठपुतली सरकार के सदर हमीद करजई और अधिक आइसोलेट हो चुके हैं। यूएनओ की कथित निगरानी में अफ़गानिस्तान में अब्दुल्ला अब्दुल्ला को जिस तरह से चुनाव में पराजित होना पड़ा साथ ही चुप रहने के लिए विवश भी होना पड़ा वह अमेरिका की लोकतंत्र में गहन आस्था की बेमिसाल कथा है।

प्रेसिडेंट हमीद करजई की अफ़गान सरकार किस क़दर बेईमान और भ्रष्ट सरकार है कि अमेरिकी फौज़ के कमांडर इन चीफ़ एडमिरल माइक मुलन को आखिरकार कहना ही पड़ा कि प्रेजिडेंट हमीद करजई को अब भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों को तुरंत गिरपफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन ने साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान की नक़ारा और भ्रष्ट सरकार के लिए उनके सैनिक अपने प्राणों की आहुति नहीं देगें। उल्लेखनीय है कि इस वक़्त तकरीबन एक लाख पचास हजार अमेरिकन और यूरोपियन सैनिक अफगानिस्तान की जंग में शिरक़त कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अमेरिकन फौज़ी कमांडर जनरल स्टैनले माइक्सटल ने प्रेसिडेंट ओबामा से पचास हज़ार सैनिकों को भेजने की गुज़ारिश की है, जिसकी मंजूरी अमेरिकी प्रशासन से भी हासिल हो गई है। प्रेसिडेंट ओबामा के डिफेंस सैक्रेटरी रार्बट गेट्स का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति अभी तो दीर्घकाल तक बनी ही रहेगी। प्रेसिडेंट ओबामा महोदय भी अफ़गान युद्व को एक अहम आवश्यकता क़रार दे रहे हैं। जबकि अपने डिफेंस सेक्रेटरी महोदय के विपरीत प्रेसिडेंट ओबामा का दावा है कि अठ्ठराह माह के पश्चात अमेरिका बाक़ायदा अफ़गानिस्तान से हट जाएगा। उनका कहना है कि उनकी जंग का मक़सद अफ़गानिस्तान में लिबरल डैमोक्रेसी की स्थापना है। और अब उनको अफ़गानिस्तान में एक ऐसे पार्टनर की जोरदार तलाश है जोकि एक स्थायी तौर पर एक शांत पुरअमन अप़फगानिस्तान की संरचना कर सके!

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान सदैव ही बड़े बड़े एम्पायरस की कब्रगाह साबित हुआ है। पिफर चाहे वह ब्रिटिश एम्पायर रहा हो या फिर सोवियत एम्पायर रहा और अब अमेरिकन एम्पायर का नंबर लगा है। सभी यहां से तबाह होकर निकले, कभी भी कोई इस सरज़मीन पर निर्णायक रुप से फतेहयाब नहीं हो सका। अक्टूबर सन् 2001 में तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश ने नार्थ एटालांटिक सैन्य संधि के देशों नाटो के साथ मिलकर अफ़गान जंग का आग़ाज़ किया था। उस वक़्त इस जंग का अमेरिकन मक़सद अफ़गानिस्तान में अलकायदा को तहस नहस

करना था, जिसने कि 11 सितंबर सन् 2000 में न्यूर्याक स्थित विश्व व्यापार केंद्र की गगनचुंबी इमारतों को धूल धूसरित कर दिया था। साथ ही कुछ काल के पश्चात सन् 2002 में बुश महोदय ने इराक में सद्दाम हुसैन के विरुद्व भी जंगी मोर्चा खोल दिया था। सद्दाम हुसैन का तो सफाया हो गया, किंतु अमेरिका इराकी जंग में उलझ कर रह गया। प्रेसिंडेट ओबामा ने अपने चुनावी अभियान में ही पूर्व प्रेसिडेंट बुश की इराक नीति की पुरजोर भतर्सना की थी और अमेरिकन जनमानस से वायदा किया था कि यदि वह अमेरिका के पे्रजिडेंट बने तो इस नीति का परित्याग कर देगें और अमेरिकी फौज़ को इराक से निकाल कर अपनी समूची सैन्य शक्ति को अपफगानिस्तान में अलकायदा के बरखिलाफ झोंक देगें। प्रेसिडेंट ओबामा अपना दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, किंतु अभी तक तो अपनी घोषित नीति पर अमल नहीं कर सकें हैं।

नोबेल पीस अवार्ड लेते हुए प्रेसिडेंट आबोमा ने फरमाया था कि शांति की खातिर जंग भी जरुरी है। ओबामा यक़ीनन बुश महोदय की तरह युद्वोन्मादी नहीं है। फिर भी वह बहुत कामयाब होते हुए नहीं प्रतीत हो रहे। इसी कारण उनकी अप्रतिम लोकप्रियता में बहुत तेजी के साथ गिरावट आ रही है। जंग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहद बोझिल और नाकारा बना दिया है। अब अमेरिका के केंद्रीय बैंक का आकलन है कि आगामी दो वर्षो तक अमेरिका कोई नया आर्थिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने की स्थिति में कदाचित नहीं है। जबरदस्त जंगी खर्च के कारण अभी तक भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर नहीं निकल सकी है। अमेरिका का वित्तीय और पूंजी बाजार सीधे खड़ा हो नहीं पा रहा है। बेराजगारी फिर कैसे कम हो जाए! अफगानिस्तान में जारी जंग पर अमेरिका प्रति वर्ष दो सौ अरब डालर व्यय कर रहा है, जिसमें इस वर्ष सौ अरब डालर की बढोत्तरी की संभवना है। इराक की जंग में अमेरिका तकरीबन सात सौ अरब डालर प्रतिवर्ष व्यय करता रहा है। इस तरह प्रतिवर्ष तकरीबन एक हजार अरब डालर का जंगी बोझ अमेरिकी अर्थव्यवस्था वहन कर रही है। प्रत्येक अमेरिकी सैनिक पर लगभग दस लाख डालर का सैन्य व्यय आता है।

अमेरिकी कांग्रेस के बहुत असरदार सदस्य डेविड ओबे और विसकोंसिन ने प्रेसिडेंट आबोमा के बरखिलापफ अमेरिकी जनता से वादा खिलापफी करने का आरोप लगाया है। इन अमेरिकी सांसदो का कहना है कि अमेरिकी सरकार चौदह सौ अरब डालर को वित्तीय घाटा अब सहन नहीं कर पा रही है, तभी तो सरकार को अपने बांड और ट्रेजरी बिल तक बेचने पड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ओबामा से समूची दुनिया ने बहुत सी उम्मीदें बांधी है जोकि पूरी होती प्रतीत नहीं हो रही हैं। अपने पूर्ववर्ती अमेरिकन प्रेज़िडेंट की तरह है, आबोमा महोदय भी अप़फगान जंग में पाक़िस्तान पर जरुरत से कुछ ज्यादा ही भरोसा करके चल रहे हैं। चीन और जापान से जंग के लिए कर्जा लेकर अमेरिका पाकिस्तान को खरबों डालर की आर्थिक मदद कर रहा, ताकि वह जंग में अलकायदा के विरुद्व एक अमेरिका के एक विश्वस्त सहयोगी का किरदार निभा सके। इस बात की गारंटी के लिए अमेरिकन संसद में कैरी-लागर बिल लाया गया ताकि इस तथ्य को मॉनिटर किया जा सके कि अमेरिकी इमदाद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न होकर सिपर्फ तालीबान और अलकायदा के ही विरुद्व ही किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकमरान तो अपनी फितरत से बहुत मजबूर रहे हैं और आजकल भी बाकायदा कश्मीर में प्रायोजित ज़ेहादी आतंकवाद का संचालन कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ओबामा पाकिस्तानी शासकों को भारत के विरुद्व अपनी आतंकवादी कारगुजारियां रोक देने के लिए विवश नहीं कर सकें हैं। भारत तो अफगानिस्तान की हकुमत को अभी तक तकरीबन सात हजार करोड़ की आर्थिक मदद दे चुका है और आगे भी मदद के लिए तैयार है क्योंकि जेहादी आतंकवाद के हाथों विगत बीस वर्षो सबसे अधिक जख़्म भारत ने ही तो झेले हैं।

प्रभात कुमार रॉय

(पूर्व प्रशासनिक अधिकारी)